करता है। यदि इस उम्र में युवाओं को राजनीति में आने का प्रोत्साहन मिलेगा, तो वे आगे आएँगे और इस संसद की ऊर्जा को 100 गुना बढ़ाएँगे। नए भारत की नींव रखने के लिए हमें युवा भारतीयों की भागीदारी चाहिए। मैं सरकार से यह माँग करता हूँ कि वह इस तरफ ध्यान दे।

Demand for restoration of license of Delhi Milk Scheme

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) के दूध में कास्टिक सोडा मिलने के बाद भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा इसका लाइसेंस 13 अक्टूबर, 2023 को निलंबित कर दिया गया, जिसके कारण डीएमएस दूध का उत्पादन और सप्लाई बंद है। डीएमएस दूध की सप्लाई बंद होने से डा. राम मनोहर लोहिया, एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग सहित कई अस्पतालों के मरीजों को कई दिनों तक दूध की आपूर्ति नहीं हुई, मजबूरन कुछ दिनों के उपरांत मरीजों हेतु निजी कंपनियों के दूध की आपूर्ति कराई गई।

इस संयंत्र में खामियों को दूर कर अभी तक लाइसेंस बहाल नहीं किया गया है, जिसके कारण दूध का उत्पादन और आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। कभी डीएमएस दूध हेतु सुबह 4 बजे से लाइन लगती थी, पर धीरे-धीरे उसकी गुणवत्ता खराब हुई और अंततः अब उसका लाइसेंस निलंबित है। डीएमएस दूध का उत्पादन बंद होने से पहले उसके एक लाख लीटर से अधिक दूध की खपत थी। दूध की सप्लाई बंद होने से आज हजारों डीएमएस बूथ संचालक आर्थिक दबाव में हैं और बूथ से उनकी मजदूरी नहीं निकल पा रही है। यदि बूथ पर दूध की सप्लाई ही नहीं होगी तो कोई भी डीएमएस बूथ पर नहीं आएगा। ऐसे में बूथ संचालकों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि वह डीएमएस के निलंबित लाइसेंस की औपचारिकताएं अविलम्ब पूर्ण कराकर उपभोक्ताओं हेतु डीएमएस का दूध उपलब्ध कराए।

Concern over dumping of Fabrics at unfair prices in Indian market

SHRI SANJEEV ARORA (Punjab): Hon. Chairman, Sir, I stand before you today to raise a critical issue gripping the Indian textile industry--the unfair dumping of synthetic knitted fabrics in our market. This practice has created immense pressure on domestic players, jeopardizing jobs, revenue, and the very core of our production capacity.

The polyester industry, currently operating at 70 per cent, faces an unprecedented threat due to unfairly priced imports from China for the past year. Unless immediate action is taken, this threat has the potential to cripple our industry, reducing capacity to less than 50 per cent and causing widespread job and revenue losses.